



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ



Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc.lko-mef@nic.in

पत्र सं० ४बी/यू०पी०/०४/६२/२०२०/एफ.सी. 1353

दिनांक: 16.08.2022

सेवा में,

विशेष सचिव(वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Trans/41685/2020)

विषय: घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 के०वी० आगरा-ग्रेटर नोएडा पारेषण लाईन हेतु जनपद अलीगढ़ में प्रभावित 0.5464 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों का पातन, जनपद हाथरस में प्रभावित 1.7094 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 28 वृक्षों का पातन, जनपद एटा में प्रभावित 0.2243 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों का पातन, जनपद फिरोजाबाद में प्रभावित 1.1315 हे० आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों के पातन, जनपद आगरा में प्रभावित 0.4996 हे० आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों के पातन, जनपद बुलन्दशहर में प्रभावित 0.1912 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 4.3024 हे० आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 115 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव(वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-1614/81-2-2022-800(58)/2020, दिनांक-13.07.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-50/81-2-2020-800(58)/2020, लखनऊ दिनांक 26.06.2020 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.06.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी उल्लिखित शर्तों की अनुपालना विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 के०वी० आगरा-ग्रेटर नोएडा पारेषण लाईन हेतु जनपद अलीगढ़ में प्रभावित 0.5464 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों का पातन, जनपद हाथरस में प्रभावित 1.7094 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 28 वृक्षों का पातन, जनपद एटा में प्रभावित 0.2243 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों का पातन, जनपद फिरोजाबाद में प्रभावित 1.1315 हे० आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों के पातन, जनपद आगरा में प्रभावित 0.4996 हे० आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों के पातन, जनपद बुलन्दशहर में प्रभावित 0.1912 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 4.3024 हे० आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 115 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 8.6477 ha. degraded forest land (Compartment/Khasra No. Not provided, Village- Sankurikala, Ismilepur, Ikanaur, Pala, Manpur, Sofipur Tehsil- Fatehabad, Firozabad, Chakarnagar, Tundala, Etah, Aligarh, Khurja District- Agra, Firozabad, Etah, Etawah, Aligarh, Bulandshahar at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. Plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in ROW under Transmission line shall be taken up by Forest Department at the cost of user agency.
4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5. User agency shall restrict the felling of trees to 115 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

6. The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.
7. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.
8. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
9. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
10. No labour camp shall be established on the forest land.
11. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
12. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
13. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
14. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
15. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
16. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
17. The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the Court orders, provisions, rules, regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.
18. Project Completion Report and Stage-II compliance report shall be submitted within a period of 6 months of completion of project.
19. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
20. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
21. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(के०)

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, कैम्या, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, हाथरस एवं गौतमबुद्धनगर।
5. अधिकृत प्रतिनिधि, घाटमपुर ट्रांसमिशन लि० 644 एवं 644 एलखनपुर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, विकासनगर, कानपुर।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(के०)